

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या- 07/2019

<u>प्रार्थी</u>	<u>बनाम</u>	<u>अप्रार्थीगण</u>
1. विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड		1. सरपंच ग्राम पंचायत, सांतपुर। 2. श्रीमती मटुबाई पत्नि श्री रामजी बारोट के कायम मुकाम- 2.1 श्रीमती मीना पत्नि स्व. श्री लक्ष्मणलाल निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही। 2.2 श्री घनश्याम पुत्र स्व. श्री लक्ष्मणलाल निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही। 2.3 श्री दीपक पुत्र स्व. श्री लक्ष्मणलाल निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही। 2.4 श्री प्रकाश पुत्र स्व. श्री लक्ष्मणलाल निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही। 2.5 श्री वीरचन्द पुत्र स्व. श्रीमती मटुबाई निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति:-



श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी प्रार्थी की ओर से।
अप्रार्थी संख्या 2.3 व 2.5 उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 01.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 26.12.2002 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त प्रस्ताव राजस्थान पंचायती राज नियम 156 की पालना किए बिना जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता ने जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर, सिरोही

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को मुख्यमंत्री रोजगार योजना अन्तर्गत कियोस्क आवंटन पंचायतीराज विभाग के पत्रांक/एफ4(1)/पि.सी./मु.योजना/2001/892 दिनांक 25.06.2002 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश में वर्ष 2002-03 में यह कियोस्क आवंटन नियमों के विरुद्ध राजस्थान पंचायतीराज नियम 156 के अन्तर्गत जारी किया है। यह है कि प्रार्थना पत्र के संलग्न होने वाले दस्तावेज प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 06 से 10 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही प्रार्थना पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर हैं न ही सचिव द्वारा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की गई है। यह है कि आवंटन हेतु जो नक्शा बनाया जाता है उसे भी सरपंच द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में उल्लेखित पात्रता एवं पंचायत नियमों से परे जाकर प्रार्थना पत्र एवं पात्रता सम्बन्धी दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना ही नियम विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है। यह है कि आवंटित कियोस्क भूमि का बाजार दर रूपए की 25 प्रतिशत राशि अर्थात् 50.00 रूपए लेकर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया एवं राशि जमा कराने की अवधि 30 दिन निर्धारित की गई एवं उक्त निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने पर आवंटन निरस्त हो जाने का निर्णय पारित किया गया लेकिन आवंटनी द्वारा पट्टा हेतु राशि जमा नहीं करवाए जाने से विक्रय विलेख जारी नहीं किया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 26.12.2002 को निरस्त किया जाना फरमावे।

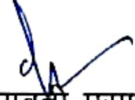
अप्रार्थी संख्या 2.3 व 2.5 की ओर से निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना फरमावे। यह है कि अप्रार्थी संख्या 2.3 ने अपने अन्य भाईयों की तरफ से भी यही निवेदन किया ।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी एवं संलग्न लगे दस्तावेजों से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या दो को ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा कियोस्क भूमि आवंटन प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 26.12.2002 को पारित किया गया। यह है कि पंचायतीराज विभाग के पत्रांक/एफ4(1)/पि.सी./मु.योजना/2001/892 दिनांक 25.06.2002 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश में कियोस्क आवंटन राजस्थान पंचायतीराज नियम 156 के अन्तर्गत जारी किया जाने का प्रावधान है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि कियोस्क आवंटन पत्रावली में प्राप्त प्रार्थना पत्र के साथ राशन कार्ड की प्रति जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, मतदाता परिचय पत्र से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह है कि आवंटन प्रार्थना पत्र के संलग्न होने वाले दस्तावेज प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 06 से 10 के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं एवं न ही प्रार्थना पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर हैं, न ही सचिव द्वारा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की टिप्पणी की गई है। यह है कि आवंटन हेतु जो नक्शा तैयार किया गया है, उस पर सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिससे उक्त नक्शे को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145(3) की पालना नहीं किया जाना प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में उल्लेखित पात्रता एवं पंचायत से परे जाकर प्रार्थना पत्र एवं पात्रता सम्बन्धी दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना नियम विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है। यह है कि आवंटित कियोस्क भूमि का बाजार दर रूपए की 25 प्रतिशत राशि अर्थात् 50.00 रूपए लेकर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया एवं राशि जमा कराने की अवधि 30 दिन निर्धारित की गई एवं उक्त निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने पर आवंटन निरस्त हो जाने का निर्णय पारित किया गया लेकिन आवंटनी द्वारा पट्टा हेतु राशि जमा नहीं करवाए जाने से विक्रय विलेख जारी नहीं किया गया।

जिला कलेक्टर, सिरौही

अतः उपरोक्त अनियमितताओं एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में पारित प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 26.12.2002 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।


(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

